

‘मेक इन इण्डिया’ योजना की दिशा एवं दशा

उषा शर्मा*

प्रस्तावना

‘मेक इन इण्डिया’ (भारत में बनाओ) योजना के वांछित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि इसमें स्थानीय उद्यमी, विदेशी निवेशक तथा अर्न्तर्देशीय संगठन आवश्यक सहयोग करें। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश भी सराहनीय सहयोग प्रदान करें। उक्त सभी तत्व मुक्त हस्त सहयोग प्रदान करेंगे तब ही इस योजना की दिशा तय होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब इस योजना का सितम्बर 2014 में शुभारम्भ किया था उस अवसर पर भारत के ख्याति-लब्ध उद्योगपति भी उपस्थित थे। योजना के सन्दर्भ में इन्होंने अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की थी तथा तत्काल निवेश की राशि की भी घोषणा की थी। कई देशों ने इस पहल में आश्वासन दिया तथा निवेश हेतु अपने हाथ आगे बढ़ाए।

संयोग अथवा दुर्संयोग देखिए उसी दिन पड़ोसी देश चीन ने भी ‘मेक इन चाइना’ कार्यक्रम का आरम्भ किया था। भारत का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के आयात को कम करना तथा निर्यात को प्रोत्साहित देना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब भारत एक “मैन्युफेक्चरिंग हब” बने। इसका आशय यह नहीं है कि भारत विदेशी माल के आयात का विरोधी है, लेकिन भारत चाहता है कि मुक्त-व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था को घाटा नहीं होना चाहिए। अतः भारतीय नीति-निर्माताओं ने भारत में निर्मित माल को विदेशों में निर्यात के उद्देश्य से “भारत में बनाओ” योजना को आधार बनाया।¹ पड़ोसी देशों के साथ भी भारत ने कई समझौते एवं करार किये हैं। इनमें अफगानिस्तान, चीन, जापान कोरिया है। उक्त सभी तथ्य योजना की भावी सफलता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रस्तुत आलेख में इन सभी तथ्यों को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था को उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि भारत में आर्थिक सुधारों (1991) के पश्चात् उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिस कारण अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि दर वर्तमान में लगभग 7.5 फीसदी बनी हुई है। साथ ही कृषि क्षेत्र की अपेक्षा उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान भी निरंतर बढ़ रहा है। विश्व बैंक द्वारा जारी वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इस दृष्टि से भारत को अपना स्तर वैश्विक परिदृश्य में ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा।

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के रूप में माना गया है। यद्यपि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास कर रही है। जिसकी वृद्धि दर 4 फीसदी से भी कम है। तथापि भारत में सरकार द्वारा किये गये क्रमिक नवीन आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक परिदृश्य में अपनी सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी आंकड़ों के अनुसार विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छोटे स्थान पर पहुंचने के क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा 2.57 फीसदी ट्रिलियन यूएस डॉलर की फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया गया है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है। यदि भारत की आर्थिक विकास दर की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था चीन को पछाड़ते हुए विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गयी है। वर्तमान में जहां चीन लगभग 6.4 फीसदी की दर से विकास कर रहा है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 7.5 फीसदी है। इस कारण आईएमएफ द्वारा भारत में निवेश की संभावनाओं को अवसरों से युक्त मानते हुए इसे ब्राइट स्पॉट के रूप में संबोधित किया गया है। यदि वैश्विक निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2018 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।²

अफ्रीकी देशों से व्यापार के संदर्भ में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा

दुनियाभर के प्रमुख देशों और बड़ी कंपनियों की दृष्टि अफ्रीका पर है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मेकिन्स के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में 10 हजार से अधिक चीनी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। चीन के भारी इन्वेस्टमेंट से अन्य देशों में, विशेषकर आज की रूचि भी बढ़ा दी है। 2006 में व्यापार में अफ्रीका के तीन बड़े पार्टनर—अमेरिका, चीन और फ्रांस थे। 2018 में चीन प्रथम, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे पायदान पर पहुंच गए। इस अवधि में भारत का व्यापार 292 फीसदी और चीन का 226 फीसदी बढ़ा। वैसे अब भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियां सबसे अधिक पूंजी लगा रही हैं, लेकिन चीन की सरकारी कंपनियों तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उसके साथ भारत और सिंगापुर के इन्वेस्टर भी प्रतिस्पर्धा में हैं।

भारत और वियतनाम ने 2020 तक 15 अरब डॉलर के व्यापार का रखा लक्ष्य

वियतनाम की यात्रा पर गये उपराष्ट्रपति एम. वैक्या नायडू ने यहां के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, हाई टेक कृषि, नवाचार, तेल और गैस उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बड़े शहरों को सीधी विमान सेवा से जोड़ने पर सहमति व्यक्त की, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शुरूआती तौर पर इस साल के अंत में 'इंडिगो' भारत तथा वियतनाम के मध्य सीधी विमान सेवा प्रारंभ करेंगी। भारत और वियतनाम दोनों देशों के मौजूदा समय में होने वाले 14 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 15 अरब डॉलर करने के लिए काम करेंगे।³

भारत—अफगानिस्तान व्यापार

अफगानिस्तान ने 24 फरवरी 2019 को ईरान के नवविकसित चाबहार बंदरगाह के द्वारा पहली बार भारत को निर्यात करना प्रारंभ किया। इससे अफगानिस्तान की विदेशी बाजारों तक पहुंच बनेगी और उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ध्यातव्य हो कि वर्ष 2017 में भारत ने सफलतापूर्वक अफगानिस्तान को चाबहार

बंदरगाह के जरिए 1.1 मिलियन टन गेहू भेजा था। इसी वर्ष द्विपक्षीय व्यापार के लिए नयी दिल्ली और काबुल के मध्य वायु गलियारा की शुरुआत की गयी थी।⁴

स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा 20 दिसम्बर को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 जारी की गई। डीआईपीपी द्वारा 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया की शुरुआत के पश्चात् पहली बार राज्य स्तर पर रैंकिंग जारी की गयी। स्टार्ट-अप इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

इसका उद्देश्य राज्यों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाना है ताकि वे अच्छी प्रक्रियाओं को सीख सकें, साझा कर सकें और उन्हें अपना सकें। साथ ही देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत कर अवकाश, इंस्पेक्टर राज से मुक्त व्यवस्था और पूंजीगत लाभ, कर की छूट प्रदान करना आदि सम्मिलित है। राज्यों का आकलन स्टार्ट-अप नीति नेतृत्व, इनक्यूबेशन हब, नवाचार, नवाचार प्रगति, संचार, पूर्वोत्तर नेतृत्व, पर्वतीय राज्य नेतृत्व इत्यादि 7 विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। इन श्रेणियों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, मार्गदर्शक, आकांक्षी मार्गदर्शक, उभरते हुए राज्य और आरंभकर्ता के रूप में पहचान की गई है।⁵

छह वर्ष पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हुई गिरावट

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पिछले छह वर्षों में पहली बार 2018-19 में गिरावट आई है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार, फार्मा में निवेश में गिरावट से एफडीआई 1 प्रतिशत गिरकर 3.08 लाख करोड़ रुपये (44,37 अरब डॉलर) रह गया। एफडीआई के मामले में सिंगापुर ने मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया। भारत में निवेश करने वाले अन्य देशों में जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस सम्मिलित है।⁶

विनिवेश से 78 हजार करोड़ रूपए का एकत्रण

केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में विनिवेश से 80,000 करोड़ रूपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अपनी भागीदारी की बिक्री करके रिकॉर्ड 77,417 करोड़ रूपए जुटाए हैं। यह तेजी एयर इंडिया के निजीकरण के साथ 2019 में भी निरन्तर रहने की प्रत्याशा है। 2018 में हुये बड़े विनिवेश सौदों में ओएनजीसी द्वारा एचपीसीएल का अधिग्रहण, सीपीएसई ईटीएफ, भारत-22 ईटीएफ और कोल इंडिया की भागीदारी बिक्री सहित 6 आरंभिक सार्वजनिक निर्गम सहित अन्य सम्मिलित है।

विगत 10 में से छह साल भारत ने लिया विश्व बैंक से सबसे अधिक कर्ज

विश्व बैंक से ऋण लेने के मामले में भारत पिछले 10 वर्षों में 6 बार शीर्ष पर रहा है। बहुपक्षीय ऋण देने वाले संस्थान की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत ने विश्व बैंक से लगभग 24.57 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया। साल 2009 से 2018 के मध्य विश्व बैंक ने सड़क और बिजली के बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत की बड़ी सहायता प्रदान की है।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है का विवरण करना यहाँ आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटनवुड सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसम्बर, 1945 को इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी, किन्तु इसने वास्तविक रूप में 1 मार्च, 1947 से कार्य प्रारम्भ किया था, वर्तमान स्थिति के अनुसार 189 राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। नौरु गणराज्य को 12 अप्रैल, 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वाँ सदस्य बनाया गया था, क्रिस्टीन लेगार्डे वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक हैं।

विश्व बैंक और भारत

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विगत 70 वर्षों (1945–2015) में बैंक से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। विगत 70 वर्षों में विश्व बैंक के दो अंगों— अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को क्रमशः 52.7 बिलियन डॉलर तथा 49.4 बिलियन डॉलर के ऋण प्रदान किए हैं।⁷

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात् 'उदार ऋण खिड़की' भी कहते हैं इसकी स्थापना 24 सितम्बर, 1960 को दी गई थी, इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है, वर्तमान में इसकी सदस्यता संख्या 173 हो गई है इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। आईडीए से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा वह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों के ही उपलब्ध कराए जाते हैं, वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कवल वही सदस्य देश ऋण पाने के पात्र है जिनकी 2012 में प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2010 के डॉलर मूल्य में) 1175 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।

इस संघ का कार्य संचालन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो विश्व बैंक का संचालन करते हैं।⁸

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में की थी, वह निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है, अर्थात् इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों के निजी क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करता है। सितम्बर 2017 के अन्त में इसकी सदस्य संख्या 184 थी, 31 जनवरी 2017 को इसकी अधिकृत पूंजी 2.58 बिलियन डॉलर थी।⁹

विश्व व्यापार संगठन

1947 में गैट की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू.टी.ओ. की स्थापना हुई। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौरे के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 1986–94 तक उरुग्वे दौरे की बातचीत का लम्बा सिलसिला चला, जिसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से सम्बद्ध बहुपक्षीय नियमों पर अनुशासन की पहुँच का बहुत विस्तार हुआ और सेवा एवं बौद्धिक व्यापार (बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार) के क्षेत्र में बहुपक्षीय नियमों की शुरुआत हुई, उरुग्वे दौरे वार्ता के कारण कृषि उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई गैट (जी.ए. टी.टी.आई.) व्यवस्था में वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई

जीएटीटीआई द्वारा निर्धारित नियमों तथा इससे सम्बद्ध समझौतों को डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को एकमुश्त समझौते के उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों के मध्य संतुलन पर विचार करने के बाद भारत सरकार में डब्ल्यूटीओ समझौते की पुष्टि की।

गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई है, आर्थिक जगत् में इसकी स्थिति अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की भांति यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है।¹⁰

एशियाई विकास बैंक

एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर 1966 में की गई थी। 1 जनवरी, 1967 को एशियाई विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ कर दिया बैंक का मुख्यालय फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में है। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक है। इस बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना है। वर्तमान में जापान के 'हारुहिको कुरोडा' एशियाई विकास बैंक के चैयरमैन है। उल्लेखनीय है कि एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष पद किसी जापानी को ही दिया जाता रहा है, जबकि इसके तीन उपाध्यक्षों में से एक अमरीका का एक यूरोप का व एक अन्य एशिया का प्रतिनिधि होता है वर्तमान में एशियाई विकास बैंक की सदस्य संख्या बढ़कर 67 हो गई है।

31 मार्च, 2017 को एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है, जिससे ऊर्जा बचत करने वाली लाइट सड़कों तथा घरेलू उपयोग में लगाने का वित्तीयन किया जाएगा साथ ही इसी ऋण से सम्पूर्ण भारत में ऊर्जा बचत करने वाले जलपम्पों की स्थापना की जाएगी।¹¹

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान सहित 8 सदस्य देश है, ढाका शिखर सम्मेलन 7-8 दिसम्बर, 1985 के निर्णयानुसार इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय काठमाण्डू में है। प्रतिवर्ष शासनाध्यक्षों का सम्मेलन किए जाने का प्रावधान है, किन्तु किसी-न-किसी कारण से इसके शिखर सम्मेलन विलम्बित होते रहे हैं। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना है। परन्तु सदस्यों राष्ट्रों के आपसी मतभेद के कारण इसके उद्देश्य की प्राप्ति पर अभी प्रश्नचिन्ह ही लगा हुआ है।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा)

दक्षेस राष्ट्रों के दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार समझौते के तहत चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के पहले चरण की प्रशुल्क कटौती को भारत ने 1 जुलाई, 2006 से लागू कर दिया है, इसके तहत 380 उत्पादों के दक्षेस देशों से आयात पर प्रशुल्क दरें घटाई गई हैं इनमें मोटर कारें, मोटर साइकिले, गोल्फ कार्ट, औषधीय उत्पाद, उर्वरक, पेंट, मॉडेम, लोहा एवं इस्पात, चुनींदा टेक्सटाइल्स उत्पाद, चुनींदा खाद्य तेल, कोको एवं कोको उत्पाद, लैक्टोस व माल्टोस आदि सम्मिलित है। दक्षेस के लीस्ट डेवलपड कंट्रीज (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एवं नेपाल) तथा नॉन लीस्ट डेवलपड कंट्रीज (पाकिस्तान एवं श्रीलंका) के मामलों में ड्यूटी में यह कटौतियाँ अलग-अलग है। इससे दक्षेस राष्ट्रों के आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी उद्योगों/किसानों की विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की दृष्टि से चुनींदा उत्पादों की एक संवेदनशील सूची भी निर्धारित कर ली गई है गैर अल्पविकसित देश के लिए 884 तथा अल्पविकसित देशों

के लिए 763 उत्पादों को इस संवेदनशील सूची में सम्मिलित किया गया है। इस सूची में सम्मिलित उत्पादों के मामले में व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम लागू नहीं होगा व्यापार उदारीकरण के तहत नॉन लीस्ट डेवलपड स्टेट्स (भारत, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) दक्षिण के अन्य देशों से आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क ही आरोपित करेंगे, जबकि अगले पाँच वर्षों में इन्हें (श्रीलंका को 6 वर्षों में) प्रशुल्क घटाकर 0.5 प्रतिशत तक लाना होगा। लीस्ट डेवलपड स्टेट्स को प्रशुल्क 30 प्रतिशत तक रखने की छूट वर्तमान में दी गई है अगले आठ वर्षों में इन्हें यह 0.5 प्रतिशत करनी होगी। मेक इन इण्डिया योजना में जिन भारतीय ने उद्यमियों सहयोग किया है उनका विवरण निम्न है¹²—

‘मेक इन इंडिया’ के उद्घाटन के अवसर पर कई भारतीय उद्योगपतियों ने इस योजना का समर्थन करते हुए इसके प्रोत्साहन हेतु तत्काल निवेश हेतु आश्वासन दिया था। वर्तमान में निम्न उद्यमियों ने इसके सहयोग प्रदान किया है—

विजय शेखर शर्मा

पेटीएम के संस्थापक एवं सीईओ का नोटबंदी से भाग्य चमका क्योंकि नोटबंदी से कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिला और शर्मा द्वारा 2010 में प्रारंभ किए गए पेमेंट गेटवे का बाजार मूल्य बढ़ा। करीब 20 करोड़ यूजर के साथ उनकी कंपनी ने भारत में गहरी जड़ें जमा ली। आज उनकी कंपनी की पूंजी पिलपकार्ट की पूंजी के करीब है।

मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीय लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। उनकी कुल सम्पत्ति 38 अरब डालर (लगभग दो लाख 47 हजार करोड़ रुपये) है। उनका मानना है कि आने वाला समय कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। 2018 में उन्होंने घोषणा की कि वह पांच करोड़ घरों को हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क जिओ गीगा फाइबर के कनेक्ट कनेक्ट करेंगे और ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी में शीर्ष पांच देशों में भारत को स्थान दिलाएंगी।

दिलीप शांघवी

सन फार्मास्यूटिकल के दिलीप शांघवी का नाम वर्तमान में समाचारों में रहा है। अमेरिका द्वारा भारतीय दवा उद्योग पर नियंत्रण लगाने का असर उनकी कंपनी पर भी पड़ा। उनकी कंपनी जेनेरिक दवा बनाने वाली दुनिया की पांची सबसे बड़ी कंपनी है। 2017 में सन फार्मा ने जापान में प्रवेश किया और रूस में अपनी उपस्थिति बढ़ाई।

अजीम प्रेमजी

भारतीय उद्योगपति, निवेशक और परोपकारी अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। उनकी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप प्रोग्राम स्पॉन्सर करती है। इसके तहत उन लोगों को शिक्षा पाने का अवसर दिया जाता है। जो देश के सुदूर जिलों में कार्य करने हेतु सहमति देते हैं।

साइरस मिस्त्री

टाटा ग्रुप के प्रमुख रहे उद्योगपति साइरस मिस्त्री टाटा संस में कुप्रबंधन के मुद्दे को उठाने और राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलिय ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अपील दाखिल करने का लेकर 2017 में खबरों में रहे। मिस्त्री ने अपील में टाटा संस को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आर्टिकल 75 को रद्द करनेका निर्देश देने की मांग की थी। जिसके अनुरूप ग्रुप को निजी कंपनी में बदलने की मांग की गई थी। मिस्त्री की कंपनी की टाटा संस में 18 प्रतिशत भागीदारी है। एनसीएलटी ने मिस्त्री के विरुद्ध और टाटा संस के पक्ष में फैसला दिया।

सचिन और बिन्नी बंसल

2017 में सचिन और बिन्नी बंसल ने बेहतर संचालन के लिए अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट को पुनर्गठित किया। फ्लिपकार्ट ने निवेशकों को द्वारा तीन अरब डॉलर (करीब 20000 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। 2018 में सचिन और बिन्नी ने अपनी कंपनी का अधिकांश नियंत्रण अमेरिका की प्रमुख कंपनी वालमार्ट को सौंप दिया।

आचार्य बालकृष्ण

पंतजलि के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व 2017 में कंपनी ने 170 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। बाबा रामदेव के साथ मिलकर प्रारंभ की गई पंतजलि में बालकृष्ण की भागीदारी 98.6 प्रतिशत है। दुनियाँ के अरबपतियों को फोर्ब्स की सूची में उनका नाम भी सम्मिलित है। पंतजलि प्रमुख ग्लोबल ब्रांडों को चुनौति दे रही है और फास्ट मूविंग कॉन्ज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र में यह सभी केवल हिन्दुस्तान यूनिलीवर से पीछे है। बालकृष्ण गुणवत्ता वाले विभिन्न तरह के उत्पादों को पेश करने में सफल रहे हैं।

साइरस पूनावाला

साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। वह यूरोप और अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीदते रहे हैं। उनके संस्थान ने 2017 में रोटावायरस का टीका लांच किया जो भारतीय अवस्था के अनुकूल है और इसे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं होती। पूनावाला महात्मा गांधी की 1931 की पेंसिल से बनाई गई दुर्लभ तस्वीर को लंदन में नीलामी में खरीदने के पश्चात् समाचारों में आए। इस तस्वीर को कलाकार जॉन हेनरी एम्शेवित्ज ने बनाया था।

रतन टाटा

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने रिटायरमेंट से लौटकर कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने साइरस मिस्त्री से कमान ले ली थी। वह दो वर्षों से भी कम समय में करीब 30 स्टार्ट अप में निवेश कर समाचारों में रहे हैं।

आनन्द महिन्द्रा

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा की पिनिन्फरिना और सांगयोंग ब्रांड के नाम से अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की योजना है। कंपनी की 2018 में चार सस्ते ई-वाहन और ई-बसें पेश करने की भी योजना है। कई अमेरिकी ट्रैक्टर असेम्बलिंग प्लांट का संचालन कर रही कंपनी अमेरिकी बाजार में पेश करने के लिए स्व-चालित ट्रैक्टर मॉडलों का परीक्षण कर रही है। कंपनी ने यूडब्ल्यूसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप के फंड के लिए स्कोले मंडी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप किया है।

उदय कोटक

कोटक महिन्द्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक सेबी द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन थे जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में की गई शिफारिशों में स्वतंत्र निदेशकों को अधिक अधिकार देना, चेयरमैनशिप को नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तक सीमित करने और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देने की बातें सम्मिलित हैं।

एन. चन्द्रशेखरन

टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चन्द्रशेखर पहले टीसीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनका मानना है कि भारतीय बाजार दुनिया में सबसे तेज विकसित होने वाला बाजार बनने जा रहा है और टाटा ग्रुप को भारत के आर्थिक विकास में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने यह राय भी प्रकट की कि टाटा ग्रुप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उसकी कंपनियां अपनी पूरी संभावनाओं को समझ सकें। कंपनी ने इंजन बनाने वाली सीएफएम इंटरनेशनल के लीप इंजन के पार्ट्स संयुक्त रूप से निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक समझौता किया है।

नंदन निलेकणी

इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। जिसने बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार को प्रारंभ किया और जो इसका संचालन करता है। विशाल सिक्का के हटने के पश्चात् नंदन निलेकणी की सेवानिवृत्ति से वापस बुलाया गया और उन्हें फिर से इंफोसिस का चेयरमैन बनाया गया। पारंपरिक एप्लीकेशन्स डेवलपमेंट और मेंटीनेंस पर फोकस करते हुए उनसे इंफोसिस के लिए नई रणनीति बनाने की अपेक्षा है। नंदन निलेकणी और उनकी पत्नी ने बिल और मेलिंडा गेट्स द्वारा चलाए आंदोलन से जुड़कर संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत उन्होंने अपनी 50 प्रतिशत संपत्ति दान करने का संकेत दिया है।

सुनील भारती मित्तल

भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अपनी पारिवारिक संपत्ति का 10 प्रतिशत परोपकारी कार्यों के लिए देने का संकल्प लिया है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा दिलाने के लिए सत्य भारती यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव किया है। उनकी कंपनी सत्य भारतीय स्कूल प्रोग्राम चला रही है। जिओ के आने के पश्चात् अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए भारती एयरटेल अधिग्रहण में जुट गई है। उसने टाटा ग्रुप के वायरलेस फोन बिजनेस और भारत में टेलीनोर के संचालन का अधिग्रहण कर लिया है। भारती एयरटेल की बाजार भागीदारी अभी 40 प्रतिशत है।

अनिल अंबानी

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी अभिषेक सिंघवी के विरुद्ध 5,000 करोड़ रूपए का मानहानि का केस कर समाचारों में रहे। सिंघवी ने अंबानी के सरकारी और निजी बैंकों से इतनी राशि के कर्ज संबंधी बयान दिया था जिसे अंबानी झूठा और छवि बिगाड़ने वाला बताते हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बोली के आधार पर बांग्लादेश में बिजली संयंत्र लगाने का 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन ने मुकेश अंबानी के जिओ के आने के चलते अपनी 2जी सेवा बंद करने का फैसला किया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 44000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

संजीव गोयनका

गोयनका ग्रुप के संजीव गोयनका आईआईटी-खड़गपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन पुनः चुने गए हैं। वह दूसरी बार यह कार्य करेंगे।। इससे पहले वह 2001-07 में चेयरमैन रह चुके हैं। आईपीएल टीम राइजिंग पूर्ण सुपरजेंट्स के मालिक रहे संजीव गोयनका एमएस धोनी को कम्पनी से हटाकर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाने पर खबरों में आए। गोयनका ग्रुप अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है और वह बिजली वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और बीकानेर में बिजली वितरण की फ्रेंचाइजी चलाती है।

राजीव बजाज

उद्योगपति राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज ने ब्रिटेन के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के साथ साझेदारी की है जिसके वसाथ बजाज ऑटो लिमिटेड ट्रयम्फ मोटरसाइकिल का संयुक्त रूप से निर्माण करेंगी। बीएस-3 से बीएस-4 वाहनों के होने के चलते 2017-18 की पहली तिमाही में बजाज ऑटो की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। उनकी कंपनी में हाल ही में बाजार में नई मोटरसाइकिल लांच की है। सरकारी प्रक्रियाओं के चलते चारपहिया वाहन लांच करने की उनकी योजना में देरी हुई है।

कुमार मंगलम बिड़ला

आदित्य बिड़ला ग्रुप और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिड़ला। रिलायंस जिओ से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया का विलय किया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय उद्योगपतियों ने 'मेक इन इंडिया' पहल ने अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया है तथा विदेशों में भी भारतीय साख स्थापित की है। इससे प्रभावित होकर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश हेतु उत्सुक हैं।

सारत: यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भारत को अग्रणी 'मेन्यूफैक्चरिंग हब' बनाने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी उसी दिन 'मेक इन चाइना' योजना की घोषणा की है। इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और चीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के रूप में माना गया है। यद्यपि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास कर रही है। जिसकी वृद्धि दर 4 प्रतिशत से भी कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था जी.डी.पी. के आंकड़ों के अनुसार विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

निवेश के क्षेत्र में छह वर्ष पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2018-19 में गिरावट दिखाई दी है। भारत में निवेश करने वाले देशों में -मॉरीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, अमेरिका तथा जापान है। सन् 2018-19 में विनिवेश से 78 हजार करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। भारत ने विगत दस वर्षों में विश्व बैंक से सबसे अधिक ऋण लिया है। कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संभल रही है और विश्व स्तर पर अपना स्थान बना रही है। जिन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है उनमें प्रमुख रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन-अंकटाड प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की भूमिका भी सराहनीय रही है। 'मेक इन इंडिया' के सफल संचाल में जिन प्रमुख उद्योगपतियों की भूमिका रही है उनमें मुख्यतः पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी, सन् फार्मास्यूटिकल के दिलीप शांघवी, विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन अजीम प्रेमजी, टाटा ग्रुप के प्रमुख साइरस मिस्त्री, पिलप कार्ट कंपनी के सचिन एवं बिन्नी, पंतजलि के आचार्य बालकृष्ण, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला, टाटा ट्रस्ट के रतन टाटा, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनन्द महिन्द्रा इंपोसिस के सह संस्थापक नंदन निलेकणी, दानवीर सुनील भारती, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी इनके अतिरिक्त राजीव बजाज ने ब्रिटेन के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल से साझेदारी की है तथा आदित्य बिड़ला ग्रुप और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन कुमार मंगलम का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सराहनीय रहा

है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की दिशा एवं दशा उज्ज्वल प्रतीत होती है क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियां निवेश हेतु उत्सुक हैं तथा स्थानीय उद्यमी भी अपने उत्पाद निर्यात निरन्तर कर रहे हैं तथा विदेशों में अपनी पैठ जमा चुके हैं। कई उद्योगपतियों ने दानदाता के रूप में अपनी निजी संपत्ति को भी देश के विकास हेतु समर्पित करने का संकल्प लिया है। यह भारतीय विकास योजनाओं के प्रति दृढ़ विश्वास निश्चित रूप से योजनाओं को आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महर्षि राजीव: भारत – 2019ए मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1–6–107
2. पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.: भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018, पृ.सं. 54
3. सिंह एच.डी. राव मित्रा: भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019–20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 53
4. सिंह एच.डी. राव मित्रा: भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019–20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 54
5. महर्षि राजीव: भारत – 2019, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1–6–106
6. सिंह एच.डी. राव मित्रा: भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019–20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 55
7. सिंह रहीस: वैश्विक संबंध, डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 102
8. सिंह रमेश: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.3
9. महर्षि राजीव: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.5
10. महर्षि राजीव: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.7
11. सिंह रमेश: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.6
12. महर्षि राजीव: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1.11.227–229.

